

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 302 | श्री विजयपुरम, गुरूवार, 12 नवंबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए



चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 में श्री विजयपुरम को मिला विशेष पुरस्कार

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

श्री विजयपुरम शहर को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 पुरस्कार समारोह में "स्वच्छ शहर–केंद्रशासित प्रदेश (5 या उससे कम शहरी स्थानीय निकायों वाले)–आशाजनक स्वच्छ शहर" श्रेणी के अंतर्गत विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

यह पुरस्कार सुश्री पूर्वा गर्ग, भा.प्र.से., सचिव (शहरी विकास), श्रीमती वसंता, अध्यक्षा, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद, श्री कमलेश्वर राव एस., भा.प्र.से., सचिव, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद तथा श्री अविनाश कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने प्राप्त किया।

यह सम्मान शहरी स्वच्छता को सुदृढ़ बनाने, ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, स्वच्छता संबंधी पहलों, जनभागीदारी तथा समग्र स्वच्छ शहरी वातावरण में सुधार लाने की दिशा में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।





यह पुरस्कार श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सभी सफाईमित्रों को समर्पित है, जिनके अथक प्रयासों और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के प्रति समर्पण ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, यह पुरस्कार श्री विजयपुरम के नागरिकों को भी समर्पित है, जिन्होंने स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर के निर्माण की दिशा में सक्रिय भागीदारी, सहयोग और सामूहिक प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।

श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सभी संबंधित विभागों, स्वच्छता कर्मियों, हितधारकों तथा नागरिकों के निरंतर सहयोग और योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि स्वच्छ एवं सतत शहर के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में श्री विजयपुरम के सफाईमित्रों और नागरिकों की सामूहिक प्रतिबद्धता तथा टीम भावना की पहचान है।

दक्षिण अण्डमान ज़िला योजना समिति की दो दिवसीय बैठक संपन्न

सभी योजना कार्यान्वयन विभागों की वर्ष 2027–2028 की प्राथमिकता आधारित ज़िला कार्ययोजना को दिया गया अंतिम रूप





श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

दक्षिण अण्डमान ज़िले की ज़िला योजना समिति (डीपीसी) की बैठक का दूसरा एवं अंतिम दिन आज ज़िला परिषद, दक्षिण अण्डमान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता दक्षिण अण्डमान ज़िला योजना समिति के अध्यक्ष एवं ज़िला परिषद के अध्यक्ष श्री पी. उम्मर ने की। बैठक में वर्ष 2027–2028 के लिए प्राथमिकता आधारित ज़िला कार्ययोजना तथा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की वर्ष 2026–2027 की प्राथमिकता आधारित कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा की गई। इसमें कैंपबेल बे के राजस्व क्षेत्रों को भी शामिल किया गया।

बैठक में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय, श्री हेमंत कुमार, भा.प्र.से., सचिव (योजना एवं वित्त), ज़िला परिषद के सदस्य, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के पार्षद तथा प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक की कार्यवाही के दौरान दक्षिण अण्डमान ज़िले एवं कैंपबेल बे के राजस्व क्षेत्रों से संबंधित वर्ष 2027–2028 की प्राथमिकता आधारित ज़िला कार्ययोजना तथा वर्ष 2026–2027 की प्राथमिकता आधारित कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जहाज़रानी, पत्तन प्रबंध बोर्ड, परिवहन, उद्योग, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन, राजकीय मुद्रणालय, स्वास्थ्य, श्रम एवं रोज़गार, ज़िला प्रशासन, जनजातीय कल्याण, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पुलिस, ज़िला कारागार, कला एवं संस्कृति, नागरिक उड्डयन, कार्मिक (नकद), वेतन एवं लेखा, विधि विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित योजनाओं पर विचार–विमर्श किया गया।

ज़िला योजना समिति के अध्यक्ष एवं दक्षिण अण्डमान ज़िला योजना समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न सुझाव एवं सिफारिशें प्रस्तुत की गईं, ताकि उन्हें संबंधित विभागों की योजनाओं में शामिल कर उनका समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। लगातार दो दिनों तक चली चर्चा के बाद सभी योजना कार्यान्वयन विभागों की वर्ष 2027–2028 की प्राथमिकता आधारित ज़िला कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही ज़िला योजना समिति की बैठक अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

डेयरी फार्म एवं गौशालाओं को पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में संचालित सभी डेयरी फार्मों एवं गौशालाओं के मालिकों और संचालकों को लागू पर्यावरणीय नियमों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जुलाई, 2021 में संशोधित 'डेयरी फार्म एवं गौशालाओं के पर्यावरण प्रबंधन संबंधी दिशा–निर्देशों' का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा मूल आवेदन संख्या 394/2022 में जारी आदेशों के अनुपालन में दिए गए हैं।

इन दिशा–निर्देशों का उद्देश्य गोबर, पशु चारे के अवशेषों तथा अपशिष्ट जल के अनुचित रखरखाव, प्रबंधन एवं निपटान से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा वैज्ञानिक एवं टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना है। सीपीसीबी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, डेयरी फार्म उन प्रतिष्ठानों को कहा जाता है, जहां दूध उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। वहीं, गौशालाएं, जिन्हें गोसदन एवं पिंजरापोल के नाम से भी जाना जाता है, कमज़ोर, बीमार, घायल, परित्यक्त एवं बेसहारा गोवंश को आश्रय एवं देखभाल प्रदान करती हैं।

इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2025 में जारी सीपीसीबी के उद्योगों के वर्गीकरण संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभिन्न प्रतिष्ठानों को लाल, नारंगी, हरे, सफेद एवं नीले वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसके तहत 500 से अधिक पशुओं वाले डेयरी फार्म लाल श्रेणी में, 101 से 500 पशुओं तथा 15 से 100 पशुओं वाले डेयरी फार्म नारंगी श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि गौशालाओं को हरी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

शेष पृष्ठ 4 पर

कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

द्वीपसमूह में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुक़सान को कम करने, बाज़ार तक पहुंच बेहतर बनाने तथा कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास अत्यंत आवश्यक है। कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) का उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन संबंधी अवसंरचना तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से जुड़ी व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराकर कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के कृषि निदेशालय ने भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप तथा अन्य पात्र लाभार्थियों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

एआईएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कृषि अवसंरचना की स्थापना एवं विकास के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके प्रमुख वित्तीय लाभ निम्नलिखित हैं:

- ब्याज में छूट: पात्र ऋणों पर 2 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत ब्याज में छूट।
- छूट की अवधि: योजना के लागू दिशा–निर्देशों के अधीन अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज में छूट उपलब्ध होगी।
- ऋण सुविधा: पात्र बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण सुविधा।

योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाएं

एआईएफ के तहत निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है:

1. फसल कटाई के बाद के प्रबंधन संबंधी अवसंरचना

- आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, जिनमें ई–विपणन मंच भी शामिल हैं।
- गोदाम एवं पैक हाउस।
- उत्पादों की गुणवत्ता जांच, छंटाई एवं श्रेणीकरण इकाइयां।
- शीत श्रृंखला एवं परिवहन सुविधाएं।
- प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र।
- फल पकाने के कक्ष।

2. सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां

- जैविक कृषि आदानों एवं जैव–उत्तेजक पदार्थों के उत्पादन की इकाइयां।
- स्मार्ट एवं परिशुद्ध कृषि के लिए अवसंरचना।
- योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्य पात्र सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति संबंधी परियोजनाएं।

इच्छुक एवं पात्र लाभार्थियों से आग्रह किया गया है कि वे व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान कर कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत विचारार्थ अपने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। प्रस्तावों में परियोजना की प्रकृति, प्रस्तावित स्थान, अनुमानित परियोजना लागत तथा वित्तपोषण संस्थान द्वारा मूल्यांकन के लिए आवश्यक अन्य संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। योजना के संबंध में अधिक जानकारी, मार्गदर्शन तथा परियोजना प्रस्ताव तैयार करने एवं जमा करने में सहायता के लिए इच्छुक किसान, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह तथा अन्य पात्र लाभार्थी अपने संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय अधिकारियों अथवा किसान कॉल सेंटर, कृषि निदेशालय, श्री विजयपुरम से दूरभाष संख्या 03192–243434 पर संपर्क कर सकते हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति में कृषि निदेशालय ने सभी पात्र हितधारकों से इस योजना का लाभ उठाने तथा कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, बाज़ार संपर्क बेहतर करने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया है।

'विरासत भ्रमण' 21 नवंबर को, पर्यटकों एवं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों से भाग लेने की अपील

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का कला एवं संस्कृति विभाग, श्री विजयपुरम एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से विरासत भ्रमण (हेरिटेज वॉक) का आयोजन करेगा। इस पहल का उद्देश्य द्वीपसमूह की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना तथा पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, विद्यार्थियों और विरासत में रुचि रखने वाले लोगों को इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। इस भ्रमण का संचालन स्थानीय इतिहासकार श्री प्रणब सरकार द्वारा किया जाएगा। 'कालापानी ट्रेल' नामक विरासत भ्रमण का आयोजन शनिवार 21 नवंबर, 2026 को प्रातः 5.30 बजे से प्रातः 7 बजे तक किया जाएगा।

भ्रमण मार्ग: मौलाना फज़ल–ए–हक़ खैराबादी का मकबरा (प्रारंभिक स्थल)–महिला बंदियों की बैरक–सरकारी प्रेस–ब्लेसिंगटन–जेएनआरएम–अबर्डीन युद्ध स्मारक शामिल हैं।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह विरासत भ्रमण सभी के लिए खुला है। इसमें पर्यटक, विद्यार्थी, स्वतंत्र पर्यटक गाइड, पैनल में शामिल गाइड, टूर ऑपरेटरों के प्रतिनिधि तथा द्वीपसमूह की विरासत को जानने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है।

इस भ्रमण के माध्यम से प्रतिभागियों को श्री विजयपुरम के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास, वास्तुकला एवं उनसे जुड़ी रोचक घटनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही, स्थानीय गाइडों एवं पर्यटन के विद्यार्थियों को इन सांस्कृतिक अनुभवों को सीखने और आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा।

इच्छुक व्यक्ति भागीदारी संबंधी जानकारी के लिए 19 नवंबर, 2026 तक कला एवं संस्कृति विभाग से संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष संख्या 03192–234775 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त artand.culture@and.nic.in पर ई–मेल भी भेज सकते हैं।

आइए, हम सब मिलकर इतिहास की इस यात्रा में शामिल हों, अपनी साझा विरासत का उत्सव मनाएं और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सांस्कृतिक पर्यटन को सुदृढ़ बनाने में योगदान दें।

जी.बी. पंत अस्पताल में राष्ट्रीय वन हेल्थ कार्यक्रम पर प्रशिक्षण दिया गया

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों एवं रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत हाल ही में जी.बी. पंत अस्पताल में राष्ट्रीय वन हेल्थ कार्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन 'अनिम्स' के निदेशक डॉ. मुकेश त्रिपाठी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में उप निदेशक (स्वास्थ्य) डॉ. अविजीत रॉय की उपस्थिति एवं प्रोत्साहन के साथ संकाय सदस्यों डॉ. अजय राज, डॉ. प्रगतेश पी., डॉ. श्वेता वी.आर., डॉ. समर हुसैन, डॉ. आंचल आनंद, डॉ. एझिलारासन तथा डॉ. मितुल साहा ने भी सहभागिता की।



प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के महत्व पर विशेष ज़ोर दिया गया। यह दृष्टिकोण मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध को मान्यता देता है। उभरते एवं पुनः उभरते संक्रामक रोगों, पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले संक्रमणों तथा बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के समक्ष उत्पन्न हो रही चुनौतियों को देखते हुए कार्यक्रम में समन्वित एवं बहुविषयक प्रयासों, एकीकृत रोग निगरानी, रोगों की शीघ्र पहचान तथा समय पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की विशिष्ट पारिस्थितिकी प्रणाली तथा उभरते संक्रामक रोगों के प्रति इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इस पहल का विशेष महत्व है।

विश्व निमोनिया दिवस आज, बाल निमोनिया की रोकथाम के लिए चलेगा विशेष अभियान

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

बचपन में होने वाला निमोनिया आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में निमोनिया भी शामिल है, जो पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) में 17.2 प्रतिशत का योगदान देता है।

बचपन में होने वाले निमोनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 12 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक 'सांस' (निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक जागरूकता एवं कार्रवाई) अभियान चलाया जाएगा। वर्ष 2026–27 के इस अभियान का नारा "निमोनिया नहीं, तो बचपन सही" रखा गया है, जो निमोनिया मुक्त बचपन के सकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। विश्व निमोनिया दिवस कल (12 नवंबर) मनाया जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य बचपन में होने वाले निमोनिया से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के संबंध में जागरूकता उत्पन्न कर इसके विरुद्ध प्रयासों को गति देना है। इसके साथ ही माता–पिता एवं देखभाल करने वालों के बीच निमोनिया के लक्षणों की शीघ्र पहचान तथा समय पर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। इस अवसर पर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (पीसीवी) के महत्व तथा घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। 'सांस' अभियान के माध्यम से समुदाय को जागरूक एवं



सक्रिय कर निमोनिया से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली आदतों और व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बचपन में होने वाले निमोनिया के कारण मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों को और गति मिलेगी।

प्राप्त विज्ञप्ति में आम जनता से अनुरोध किया गया है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया के मामलों की शीघ्र पहचान तथा समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्तर पर पहुंचने वाली एएनएम एवं आशा कार्यकर्ताओं को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

किसानों से 30 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण पूरा करने की अपील

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

कृषि विभाग ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं, सब्सिडी एवं कृषि सेवाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के लिए 30 नवंबर, 2026 तक फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण अवश्य पूरा कर लें। फार्मर रजिस्ट्री भारत सरकार के डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्रीस्टैक पहल के तहत लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक किसान की सत्यापित डिजिटल पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभों का सुचारू रूप से वितरण सुनिश्चित करना है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र प्रायोजित सभी योजनाओं (सीएसएस) का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी का पंजीकरण अनिवार्य है। मंत्रालय के निर्देशानुसार, वैध फार्मर आईडी नहीं रखने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ, जिनमें रियायती दर पर उर्वरक की बुकिंग भी शामिल है, मिलना बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित समय–सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा नहीं करने वाले किसानों को आगामी रबी मौसम 2027 से कृषि आदानों तथा पीएम–किसान योजना के लाभ प्राप्त करने में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विभाग ने सभी पात्र किसानों से निर्धारित समय–सीमा के भीतर पंजीकरण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग द्वारा द्वीपसमूह में कृषि उप–केंद्रों, निर्धारित पंजीकरण केंद्रों तथा विशेष फार्मर रजिस्ट्री शिविरों के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। किसान आवश्यक विवरण एवं संबंधित दस्तावेज़ों के साथ अपने निकटतम कृषि उप–केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) अथवा फार्मर रजिस्ट्री शिविर में जाकर अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।

कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से क्षेत्रीय कर्मचारियों को सहयोग देने तथा द्वीपसमूह में उपलब्ध पंजीकरण सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने की अपील की है, ताकि फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत शत–प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

स्वराज द्वीप में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी पर प्रशिक्षण संपन्न

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग ने भारतीय फोटोग्राफी संस्थान (आईआईपी), नोएडा के सहयोग से आज स्वराज द्वीप में विश्व बैंक सहायता प्राप्त सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने एवं गति प्रदान करने की योजना (रैम्प) के अंतर्गत फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं कैमरा संचालन पर आयोजित आठ दिवसीय गहन प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया। 3 से 11 नवंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उद्योग जगत के अनुरूप तकनीकी कौशल प्रदान करना, स्वरोज़गार के व्यावहारिक अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें संगठित सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से जोड़ना था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के विस्तृत पाठ्यक्रम में पेशेवर कैमरा संचालन, डिजिटल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्रोन इमेजिंग तथा पोस्ट–प्रोडक्शन कार्यप्रणाली को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, उभरते हुए विशिष्ट क्षेत्रों जैसे अंडरवाटर फोटोग्राफी एवं एस्ट्रो फोटोग्राफी पर विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। ये प्रशिक्षण सत्र आईआईपी, नोएडा की विशेषज्ञ



प्रशिक्षक सुश्री गरिमा चौधरी एवं श्री आसिफ खान के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्याम नगर ग्राम पंचायत के प्रधान श्री आलोक मृधा ने द्वीपों के युवाओं के लिए पर्यटन क्षेत्र में पेशेवर फोटोग्राफी के माध्यम से स्थायी एवं बेहतर आजीविका के अवसर सृजित करने की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वराज द्वीप में राष्ट्रीय स्तर का उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग की सराहना की तथा पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान समर्पण एवं लगन के साथ भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को बधाई दी। कार्यक्रम के समापन पर आठ दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

कार निकोबार के मलाका गांव में सुनामी जागरूकता कार्यक्रम संचालित

कार निकोबार, 11 नवंबर।

आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा चिह्नित 30 गांवों में आयोजित की जा रही जनसंपर्क गतिविधियों के तहत आज कार निकोबार के मलाका गांव के प्रथम मुखिया के निवास पर सुनामी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन निकोबार ज़िले के उपायुक्त कार्यालय के अंतर्गत ज़िला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय में सुनामी के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा आपदा से निपटने की तैयारियों को सुदृढ़ करना था।



कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सुनामी के खतरों, इसके कारणों एवं संभावित प्रभावों, प्राकृतिक चेतावनी संकेतों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के साथ–साथ सुनामी संबंधी चेतावनियों एवं आपातकालीन संचार व्यवस्थाओं के बारे में जागरूक किया गया। समुदाय के लोगों को निर्धारित निकासी मार्गों, सुरक्षित स्थानों तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई। इस दौरान विशेष रूप से परिवार स्तर पर आपदा की तैयारी, आपातकालीन किट तथा आवश्यक सुरक्षा उपायों पर ज़ोर दिया गया।

प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी शंकाओं का समाधान करने का अवसर मिला तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। स्थानीय समुदाय एवं संबंधित हितधारकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहयोग प्रदान किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आपदा प्रबंधन निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इनकॉयस) तथा दक्षिण अण्डमान, उत्तर व मध्य अण्डमान और निकोबार के ज़िला प्रशासनों के समन्वय से ये जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

भारी वर्षा का अनुमान

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 12, 13, 14 एवं 15 नवंबर को एक–दो स्थानों पर भारी वर्षा (07 से 11 सेमी) होने की बहुत अधिक संभावना है। इसके साथ ही 12, 13, 14 एवं 15 नवंबर को द्वीपसमूह के एक–दो स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने, बिजली चमकने तथा गरज के साथ तूफान आने की बहुत अधिक संभावना है। वहीं, 16 एवं 17 नवंबर को एक–दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने, बिजली चमकने तथा गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। आपदा प्रबंधन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार 12 नवंबर, 2026 से 15 नवंबर, 2026 तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के तटों के आसपास समुद्र में मौसम के प्रतिकूल रहने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कभी–कभी इनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 11 नवंबर, 2026 से 15 नवंबर, 2026 तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के तटों के आसपास समुद्र में नहीं जाएं। इस दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। नौकाओं का संचालन अत्यंत सतर्कता के साथ करने तथा मनोरंजन संबंधी समुद्री गतिविधियों में भी पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानकीकरण पर कार्यशाला आयोजित

चेन्नई/श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), चेन्नई शाखा कार्यालय द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के सहयोग से हाल ही में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय में मानकीकरण पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, सरकारी अधिकारियों तथा औद्योगिक कर्मियों के बीच भारतीय मानकों, गुणवत्ता, सुरक्षा, मानकीकरण एवं उपभोक्ता संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के निदेशक (नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी के बीच गुणवत्ता के प्रति जागरूकता एवं मानकीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के पहले दिन का आयोजन विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक प्रतिभागियों के लिए किया गया, जिसमें लगभग 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बीआईएस, चेन्नई शाखा कार्यालय के वैज्ञानिक–सी व उप निदेशक श्री साई चंद्रा ने उन्हें कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।

बीआईएस, चेन्नई शाखा कार्यालय के वैज्ञानिक–सी व उप निदेशक श्री पक्की बालू ने तकनीकी सत्र में भारतीय मानकों के निर्माण में बीआईएस की भूमिका, उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रमाणन तथा दैनिक जीवन में मानकों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यशाला के दूसरे दिन सुबह का सत्र नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के



सरकारी अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के उप निदेशक (नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) श्री राजेश कुमार ने सत्र का उद्घाटन किया तथा सरकारी कामकाज, जनसेवा वितरण एवं उपभोक्ता संरक्षण में भारतीय मानकों की प्रासंगिकता पर ज़ोर दिया।

बीआईएस, चेन्नई शाखा कार्यालय के वैज्ञानिक–सी व उप निदेशक श्री साई चंद्रा एवं श्री पक्की बालू ने संयुक्त रूप से तकनीकी सत्र आयोजित किए। इस दौरान उन्होंने बीआईएस की भूमिका एवं कार्यों की जानकारी दी तथा गुणवत्ता और मानकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस एवं सरकारी विभागों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

इसके अतिरिक्त, बीआईएस, चेन्नई शाखा कार्यालय के वैज्ञानिक–सी व उप निदेशक द्वारा औद्योगिक कर्मियों के लिए भी एक कार्यशाला आयोजित की गई।

डेयरी फार्म एवं गौशालाओं को पर्यावरणीय ——————————पृष्ठ 1 का शेष

अनिवार्य पर्यावरणीय अनुपालन

सभी डेयरी फार्मों एवं गौशालाओं के मालिकों और संचालकों को निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करना होगा:

1. सीपीसीबी के दिशा–निर्देशों का अनुपालन: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एवं जुलाई, 2021 में संशोधित डेयरी फार्म एवं गौशालाओं के पर्यावरण प्रबंधन संबंधी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

2. गोबर का वैज्ञानिक प्रबंधन: परिसर में उत्पन्न होने वाले गोबर का उचित संग्रहण, उपचार एवं वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए खाद निर्माण, केंचुआ खाद निर्माण, जैव–मिथेनीकरण अथवा गोबर के लट्ठे बनाने जैसी उपयुक्त तकनीकों को अपनाया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से गोबर को उचित प्रबंधन के लिए संबंधित स्थानीय निकाय को सौंपना होगा।

3. अपशिष्ट जल का प्रबंधन: डेयरी फार्मों एवं गौशालाओं से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उचित संग्रहण एवं पर्याप्त उपचार सुनिश्चित करना होगा। बिना उपचारित अपशिष्ट जल को पर्यावरण में छोड़ना अथवा ज़मीन में रिसने देना प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे भूजल प्रदूषित हो सकता है।

4. पशुओं के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था: सीपीसीबी के लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पशु के खड़े होने, आराम करने, स्वतंत्र रूप से घूमने–फिरने एवं चारा खाने के लिए पर्याप्त स्थान तथा उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

5. वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करना: लागू सहमति संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को स्थापना से पहले जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत एएनपीसीसी से स्थापना की सहमति (सीटीई) तथा संचालन शुरू करने से पहले संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त करनी होगी। इसके लिए संबंधित स्थानीय निकायों से पूर्व पंजीकरण कराना भी आवश्यक है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एएनपीसीसी ने सभी डेयरी फार्मों एवं गौशालाओं के मालिकों और संचालकों को उपर्युक्त पर्यावरणीय आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा एएनपीसीसी से आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा सकता है।

राज्य पुस्तकालय में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 14 से 20 नवंबर तक

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

राज्य पुस्तकालय, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम में 14 से 20 नवंबर तक 'राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 2026' मनाया जाएगा। सप्ताहभर चलने वाले इस आयोजन के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय द्वारा कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गों के लिए पुस्तक प्रदर्शनी के साथ–साथ विभिन्न साहित्यिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें चित्रकला, निबंध लेखन, भाषण एवं कहानी सुनाने जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। यह प्रदर्शनी 14 से 20 नवंबर तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।

एम.वी. स्वराजद्वीप का आगमन एवं प्रस्थान

श्री विजयपुरम, 11 नवंबर।

यात्री जहाज़ एम.वी. स्वराजद्वीप 16 नवंबर, 2026 को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान की लोडिंग 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। अतिरिक्त सामान व माल की बुकिंग पहले से ही डीएसएस के वाणिज्यिक विभाग में कराना अनिवार्य है।

जहाज़रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यात्रियों के जहाज़ पर चढ़ने की प्रक्रिया 16 नवंबर को सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक शुरू रहेगी। निर्धारित प्रस्थान समय से एक घंटे पहले यात्रियों के जहाज़ पर चढ़ने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। देर से पहुंचने वाले यात्रियों को जहाज़ पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच विशाखापत्तनम से रवाना हुआ यात्री जहाज़ एम.वी. स्वराजद्वीप 12 नवंबर, 2026 को सुबह 7.30 बजे श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। जहाज़ में 4 शिशुओं सहित कुल 365 यात्री सवार हैं। श्री विजयपुरम पहुंचने पर जहाज़ को हैडो घाट पर खड़ा किया जाएगा तथा यात्रियों को तुरंत जहाज़ से उतारा जाएगा।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

भारतीय नौसेना अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल–26 के पांचवें संस्करण का समन्वय करेगी

नई दिल्ली, 11 नवम्बर। इंडियन नेवी, देश की समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा तैयारियों का आकलन करने और उन्हें मज़बूत करने के लिए 11 से 19 नवंबर, 2026 तक पूरे भारत में होने वाली कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज़ सी विजिल–26 के पांचवें एडिशन को कोऑर्डिनेट करेगी। यह एक्सरसाइज़ दो फेज़ में होगी। कोस्टल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रेडीनेस इवैल्यूएशन फेज़ 11 से 17 नवंबर तक होगा, इसके बाद सी फेज़ 18 और 19 नवंबर को होगा। 2018 में शुरू किया गया सी विजिल, 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत की समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए शुरू किए गए उपायों को सही ठहराने के लिए शुरू किया गया था। 2026 एडिशन में पूरे भारतीय समुद्र तट और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को कवर किया जाएगा, जिसमें सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही मछली पकड़ने वाले और तटीय समुदायों सहित विभिन्न समुद्री हितधारक शामिल होंगे।

सचिन तेंदुलकर के 26 ऐतिहासिक बल्ले अब मुंबई क्रिकेट संग्रहालय में होंगे प्रदर्शित

मुंबई, 11 नवंबर (हि.स.)। भारतीय क्रिकेट की विरासत को सहेजने और खेल के इतिहास को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपने करियर के कुछ सबसे खास बल्ले और यादगार वस्तुएं मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) को भेंट करेंगे। इनमें वे बल्ले भी शामिल हैं, जिनसे उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के 100 शतक लगाए थे। इन सभी वस्तुओं को एमसीए के शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इस विशेष संग्रह का अनावरण 16 नवंबर 2026 को एक समारोह में होगा।



यह तारीख सचिन तेंदुलकर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के 13 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है। उन्होंने 16 नवंबर 2013 को अपने घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 200वां टेस्ट मैच खेलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था।

इस अवसर पर संग्रहालय में पहली बार अपनी तरह की एक विशेष प्रदर्शनी 'बैटोग्राफी' शुरू की जाएगी। इसमें तेंदुलकर के करियर के 26 बल्लों के साथ उनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण यादगार वस्तुएं प्रदर्शित होंगी। 'बैटोग्राफी' नाम जीवनी की अवधारणा से प्रेरित है। इसके माध्यम से मास्टर ब्लास्टर के क्रिकेट सफर को उन बल्लों की कहानी के जरिये प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनके करियर के ऐतिहासिक और यादगार पलों के साक्षी रहे हैं। प्रत्येक बल्ला उनके शानदार करियर के एक खास अध्याय को दर्शाएगा। इससे क्रिकेट प्रेमियों को उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों के पीछे की कहानी को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।

बल्लों के अलावा सचिन के करियर के महत्वपूर्ण अवसरों और उपलब्धियों से जुड़ी कई अन्य यादगार वस्तुएं भी प्रदर्शनी का हिस्सा होंगी। इनमें हेलमेट, जर्सी, नोट्स सहित अन्य संग्रहणीय वस्तुएं शामिल हैं। संग्रहालय में इसके लिए एक विशेष स्थान तैयार किया गया है, जो तेंदुलकर के असाधारण क्रिकेट सफर को समर्पित होगा। इस प्रदर्शनी के जरिये प्रशंसक उनके करियर के ऐतिहासिक पलों, उपलब्धियों और यादों को फिर से करीब से देख सकेंगे।

पुरी में पहली बार आयोजित होने वाली सड़क और रेत की मैराथन में धावकों के लिए कुल 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार रखा गया

नई दिल्ली, 11 नवम्बर। पवित्र तटीय शहर पुरी, देश भर से और उससे भी आगे से दौड़ के शौकीनों, कुलीन एथलीटों और फिटनेस प्रेमियों का एक असाधारण खेल अनुभव के लिए स्वागत करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत की पहली सड़क–प्लस–रेत मैराथन, ओएमसी पुरी तटीय मैराथन, रविवार, 13 दिसंबर, 2026 को आयोजित होने जा रही है।



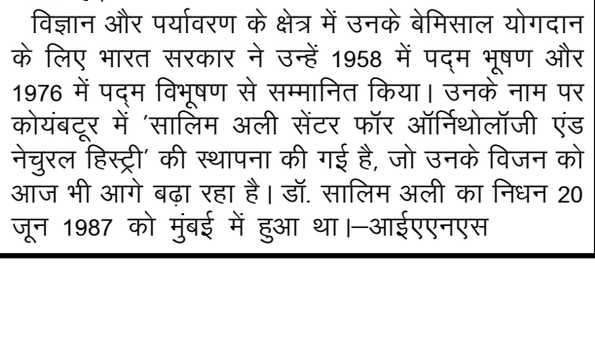
प्रतिस्पर्धी दौड़, तटीय सौंदर्य, सांस्कृतिक अन्वेषण और सामुदायिक भागीदारी का एक अनूठा संयोजन पेश करते हुए, यह आयोजन भारत में मैराथन के अनुभव को पूरी तरह से नया रूप देने का वादा करता है, जिसमें 1 करोड़ रुपये की कुल पुरस्कार राशि दांव पर लगी है। पंजीकरण 14 नवंबर, 2026 को बंद होने वाले हैं, इसलिए इच्छुक प्रतिभागियों के पास इस अनूठे खेल आयोजन में अपनी जगह पक्की करने के लिए सीमित समय है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धावक चार दौड़ श्रेणियों – 42 किमी, 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी में से किसी एक को चुन सकते हैं, जो अनुभवी मैराथन धावकों, प्रतिस्पर्धी एथलीटों, फिटनेस के शौकीनों और पहली बार दौड़ने वाले धावकों के लिए उपयुक्त हैं।

इस आयोजन को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है क्योंकि मनोरंजन जगत और भारतीय खेल जगत की कई जानी–मानी हस्तियों ने इसका उत्साहजनक समर्थन किया है। बॉलीवुड सितारे अजय देवगन, राजकुमार राव, मंजरी फडनीस, शरद मल्होत्रा घ्छऔर अर्चना सिंह के साथ–साथ हास्य कलाकार कपिल शर्मा ने भी लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करके इस अभियान में अपना योगदान दिया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, ओलंपियन अनुराधा बिस्वाल, पूर्व भारतीय भारोत्तोलक के. रवि कुमार और भारतीय पैरा–एथलीट सुचित्रा परिदा जैसी खेल हस्तियों के समर्थन से उनका सहयोग और भी मजबूत हुआ है।

फिटनेस एंबेसडर और दौड़ के शौकीन मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर भी मैराथन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को फिटनेस अपनाने और पुरी में दौड़ने के अनूठे आकर्षण का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस मैराथन का उद्देश्य भारत के सर्वश्रेष्ठ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त धावकों को एक साथ लाना है, साथ ही सभी फिटनेस स्तरों के प्रतिभागियों के लिए अपने द्वार खोलना है। यह सिर्फ एक दौड़ से कहीं बढ़कर है, यह ब्रह्मांड के स्वामी की पवित्र भूमि पर दौड़ने का अवसर प्रदान करता है, जो खेल की उपलब्धि की भावना को ओडिशा की आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के साथ जोड़ता है। पंजीकरण 14 नवंबर, 2026 को बंद हो जाएंगे। –(एएनआई)

राष्ट्रीय पक्षी दिवस : एक गौरैया की मौत ने बदली थी जिंदगी, ऐसे बने सालिम अली भारत के 'बर्डमैन'

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। हर साल 12 नवंबर को भारत के 'बर्डमैन' यानी डॉ. सालिम अली की जयंती को देश में 'राष्ट्रीय पक्षी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 1896 में जन्मे सालिम अली वह शख्सियत थे, जिन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान को एक नई पहचान दी और प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते को एक बिल्कुल नया और संवेदनशील नजरिया दिया।



सालिम अली के जीवन का टर्निंग पॉइंट बड़ा ही दिलचस्प है। बचपन में उनके पास एक एयर गन हुआ करती थी। एक दिन खेलते–खेलते उनकी बंदूक से एक गौरैया को गोली लग गई। जब उन्होंने उस मृत पक्षी को उठाया, तो देखा कि उसके गले पर एक अजीब–सा पीला निशान था। इस 'पीले गले वाली गौरैया' ने उनके मन में इतने सवाल पैदा कर दिए कि वे अपने चाचा अमीरूद्दीन तैयबजी के साथ उसे लेकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) पहुंचे।

वहां के मानद सचिव डब्ल्यू. एस. मिलार्ड ने न सिर्फ उनकी जिज्ञासा शांत की, बल्कि उन्हें पक्षियों के शानदार कलेक्शन से भी रूबरू कराया। यह वही पल था, जिसने एक आम बच्चे की भारत का सबसे महान पक्षी–विज्ञानी बनने की यात्रा को शुरू किया। उनकी मशहूर आत्मकथा 'द फॉल ऑफ ए स्पैरो' इसी घटना पर आधारित है।

डॉ. सालिम अली ने भारत में पहली बार पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण शुरू किया था। उस दौर में, जब पक्षियों को देखना महज़ एक शौक या शिकार का हिस्सा माना जाता था, सालिम अली ने इसे एक गंभीर विज्ञान में बदल दिया। उनके पास कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनका जुनून किसी भी डिग्री से बड़ा था। जर्मनी में प्रशिक्षण लेने के बाद, जब वे भारत लौटे, तो उन्होंने अपनी दूरबीन और नोटबुक के साथ जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों की खाक छाननी शुरू कर दी।

1941 में छपी उनकी किताब 'द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स' ने आम लोगों को पक्षियों की दुनिया से जोड़ा। यह किताब आज भी वाइल्डलाइफ और बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए किसी बाइबल से कम नहीं है। इसके अलावा, अमेरिकी वैज्ञानिक एस. डिल्लन रिप्ले के साथ मिलकर लिखी गई उनकी 10 खंडों वाली 'हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान' पक्षी–विज्ञान के क्षेत्र में एक मास्टरपीस मानी जाती है।

उनका विजन सिर्फ पक्षियों पर रिसर्च करने तक सीमित नहीं था। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए राजनेताओं से भी भिड़ जाने का माद्दा रखते थे। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनका पत्राचार काफी मशहूर है। केरल के समृद्ध 'साइलेंट वैली नेशनल पार्क' को एक हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बचाने और राजस्थान के भरतपुर स्थित 'केवलादेव नेशनल पार्क' (भरतपुर बर्ड सेंचुरी) की स्थापना में उनका सबसे अहम रोल रहा। भरतपुर आज दुनिया भर के प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है, जिसका बहुत बड़ा श्रेय सालिम अली की दूरदर्शिता को जाता है।

विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके बेमिसाल योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर कोयंबटूर में 'सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री' की स्थापना की गई है, जो उनके विजन को आज भी आगे बढ़ा रहा है। डॉ. सालिम अली का निधन 20 जून 1987 को मुंबई में हुआ था।–आईएएनएस

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 नए एम्स स्वीकृत, 18 संस्थान पूरी तरह कार्यरत

नई दिल्ली, 11 नवम्बर। भारत सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स के नेटवर्क का विस्तार कर रही है, ताकि किफायती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य विशेषज्ञतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ–साथ देश में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के तंत्र को भी मजबूत करना है।

पीएमएसएसवाई के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 18 पूरी तरह कार्यरत हैं। इन संस्थानों में ओपीडी और इनपेशेंट विभाग (आई पी डी) सेवाओं के साथ–साथ आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवाएं, जांच एवं निदान सुविधाएं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) के तहत स्थापित नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में 2021–22 से 31 अक्टूबर 2026 तक पांच वर्ष की अवधि में रूप से 6 करोड़ से अधिक बाह्य रोगी विभाग (ओ पी डी) परामर्श दर्ज किए गए हैं। यह उपलब्धि इन संस्थानों की बढ़ती पहुंच और देशभर के लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में इनके योगदान को दर्शाती है।



इन संस्थानों में बढ़ते मरीजों के आने का अंदाजा वर्षवार ओपीडी आंकड़ों से लगाया जा सकता है। ओपीडी परामर्श की संख्या से लगता है। परामर्श 2021–22 में 50.03 लाख थे जो 2022–23:में बढ़कर 77.95 लाख हो गए। वहीं 2023–24 में परामर्श 100.52 लाख थे जो 2024–25 में बढ़कर 129.98 लाख तक पहुंच गए जो 2025–26 तक 144.96 लाख पहुंच गए। 2026–27के दौरान अक्टूबर 2026 तक एम्स ने 97.41 लाख ओपीडी परामर्श दर्ज किया। इन सभी वर्षों के आंकड़ों को मिलाकर कुल संख्या लगभग 6.01 करोड़ हो जाती है।

वहीं, नए एम्स ने स्नातक, स्नातकोत्तर और नर्सिंग शिक्षा के अवसरों का भी विस्तार किया है। इसके साथ ही इन संस्थानों में विशेषज्ञतापूर्ण क्लिनिकल सुविधाओं और उन्नत चिकित्सा सेवाओं का विकास किया जा रहा है।

अंतरिक्ष, एयरोस्पेस और अनुसंधान सहयोग पर इटली के मंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

नई दिल्ली, 11 नवंबर (हि.स.)। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह बुधवार को तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर इटली के लिए रवाना हुए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री इटली के अंतरिक्ष, एयरोस्पेस और अनुसंधान सहयोग से जुड़े मंत्रियों सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अहम वार्ता करेंगे।

इस यात्रा के दौरान उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें, रोम में दूसरा भारत–इटली विज्ञान एवं नवाचार संवाद 2026 तथा ट्रिएस्टे के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के साथ संवाद आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को और बढाने का अवसर मिलेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 12 नवंबर को रोम में आयोजित होने वाला दूसरा भारत–इटली विज्ञान एवं नवाचार संवाद 2026 दोनों देशों के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों, अनुसंधान, नवाचार क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर को एक मंच पर लाएगा। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट अनुसंधान एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, अनुसंधान को नवाचार में परिवर्तित करना, संस्थागत साझेदारी को मजबूत करना तथा भविष्य में सहयोग के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करना है।

चीन सीमा पर आईटीबीपी की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैनात, बड़े पैमाने पर बन रहे भूमिगत बंकर

नई दिल्ली, 11 नवम्बर। भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपनी सभी सीमा बटालियनों में ड्रोन प्लाटून गठित की हैं। बल ने गलवन जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए 'स्ट्राइक' नामक नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। ये कदम भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन का मुकाबला करने के लिए उठाए जा रहे हैं।

आईटीबीपी के महानिदेशक (डीजी) शत्रुजीत सिंह कपूर ने हाल ही में यह जानकारी दी। राजस्थान के अलवर स्थित बल के एक केंद्र में आयोजित अलंकरण समारोह के दौरान जवानों को संबोधित करते हुए कपूर ने कहा कि आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए पारंपरिक युद्ध रणनीतियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। चीन को भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बताते हुए उन्होंने आधुनिक हथियारों, ड्रोन, ड्रोन–रोधी प्रणालियों और सीमा चौकियों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ड्रोन एक बड़ी चुनौती भी बन गए हैं और अवसर भी। ड्रोन ऐसी तकनीक हैं, जिनके जरिए एक छोटा देश भी बड़े देश को कड़ी टक्कर दे सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध में हर महीने रूस के करीब 10,000 से 15,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा– "ड्रोन आने के बाद पारंपरिक सेनाओं की भूमिका बदल गई है। हमें बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन–रोधी प्रणालियां अपनानी होंगी।" उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से मिले 400 करोड़ रुपये में से 70 प्रतिशत राशि ड्रोन युद्ध क्षमता बढ़ाने पर खर्च करने की योजना है।



इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपये की व्यापक आधुनिकीकरण योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसमें से 1,000 करोड़ रुपये ड्रोन और ड्रोन–रोधी प्रणालियों के लिए निर्धारित किए जाएंगे।

इतिहास के पन्नों में 12 नवम्बर : 1930 को लंदन में शुरू हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारत के संवैधानिक भविष्य पर हुई ऐतिहासिक चर्चा

नई दिल्ली, 11 नवम्बर। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश सरकार ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन भारत के भविष्य के संविधान पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर सभी प्रमुख दलों और भारतीय रियासतों के 73 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पहली बार था जब भारतीय और ब्रिटिश प्रतिनिधि बराबरी के स्तर पर आमने–सामने बैठे।

सम्मेलन का उद्देश्य महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन से उत्पन्न राजनीतिक दबाव को शांत करना और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। ब्रिटिश सरकार ने इस बैठक के जरिए भारत में बढ़ती स्वतंत्रता की मांग को नियंत्रित करने की कोशिश की।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन में संघीय ढांचे, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यकों, रक्षा सेवाओं और मताधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सिंध और उत्तर–पश्चिम सीमांत प्रांत को अलग करने का प्रस्ताव भी रखा गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 'अछूतों' के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की, जबकि तेज बहादुर सप्रू ने अखिल भारतीय महासंघ का विचार रखा, जिसका मुस्लिम लीग ने समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण सम्मेलन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत के संवैधानिक विकास की दिशा तय करने की शुरुआत जरूर की।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1781– अंग्रेजों ने नागापट्टनम पर क़ब्ज़ा किया।

1847– ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिंप्सन ने बेहोशी की दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफार्म का प्रयोग किया।

1918 – ऑस्ट्रिया एक गणतंत्र बना।

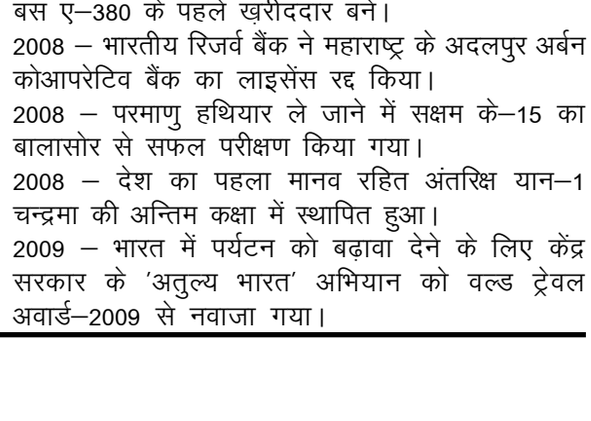
1925–अमेरिका और इटली ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1936 – केरल के मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुले।

1956 – मोरक्को, सूडान और ट्यूनिशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए।

1963 – जापान में ट्रेन दुर्घटना में 164 लोग मारे गये।

1967 – इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया।



1969 – प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अलग करने की घोषणा की गई थी।

1974 – दक्षिण अफ्रीका नस्लीय नीतियों के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा से निलंबित।

1990 – जापान में सम्राट आकिहितो का परम्परानुसार सिंहासनरोहण।

1995 – नाइजीरिया राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबित।

2001 – न्यूयॉर्क में अमेरिकी एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 260 यात्री मारे गए।

2002–संयुक्त राष्ट्र ने स्विटजरलैंड के संघीय ढांचे के आधार पर साइप्रस के लिए एक नयी शांति योजना तैयार की।

2005 – ढाका में 13वाँ दक्षेस शिखर सम्मेलन प्रारम्भ।

2005 – भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया।

2007 – सऊदी के राजकुमार अलवलीद सुपरजंबो एयर बस ए–380 के पहले ख़रीददार बने।

2008 – भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोआपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया।

2008 – परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम के–15 का बालासोर से सफल परीक्षण किया गया।

2008 – देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान–1 चन्द्रमा की अन्तिम कक्षा में स्थापित हुआ।

2009 – भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के 'अतुल्य भारत' अभियान को वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड–2009 से नवाजा गया।

भारतीय स्टेट बैंक
एचएलसी श्री विजय पुरम शाखा
जिला – दक्षिण अण्डमान

नियम 8(1) के अंतर्गत
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के संबंध में)

जहाँ,

अधोहस्ताक्षरी, भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act. 2002) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणी/जमानतकर्ताओं को मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें उनसे उक्त सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करने हेतु कहा गया था।

चूँकि ऋणी/जमानतकर्ताओं द्वारा उक्त मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अतः इसके द्वारा ऋणी/जमानतकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 10/11/2026 को प्राप्त कर लिया है।

ऋणी/जमानतकर्ताओं तथा आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें। उक्त संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी लेन–देन भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अधीन होगा, जो नीचे उल्लिखित बकाया राशि के साथ–साथ भविष्य में लगने वाले ब्याज, आनुषंगिक व्यय, लागत एवं अन्य शुल्कों सहित होगा।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता का नाम एवं बकाया राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जा प्राप्त करने की तारीख
1	(क) श्रीमती पी. नित्या (कानूनी उत्तराधिकारी), स्वर्गीय वीरा मणि की पत्नी। (ख) जमानतकर्ता : शून्य। (ग) मांग सूचना की तारीख : 04/08/2026 एवं 05/11/2026 (घ) कुल बकाया राशि : रु. **32,74,098/–**	फ्लैट संख्या B/05, द्वितीय तल, जिसका कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मीटर है, जो लोकनाथ हाउसिंग को–ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में स्थित है। उक्त संपत्ति सर्वेक्षण संख्या 94/33, ग्राम टेलराबाद, तहसील श्री विजय पुरम, जिला दक्षिण अण्डमान में स्थित है। **संपत्ति की चारों सीमाएँ :** उत्तर में : फ्लैट संख्या बी/04 दक्षिण में : सर्वे संख्या 94/32 पूर्व में : फ्लैट संख्या बी/06 पश्चिम में : सड़क/फुटपाथ	10/11/2026

दिनांक : 10.11.2026
स्थान : श्री विजय पुरम

ह./–
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

ई–निविदा सूचना

No. DB-Tender/Elect/WSD/2026-27/3411 दिनांक 10.11.2026

अ॰लो॰नि॰वि॰ ओपन टेक्नोलोजी का उपयोग करते हुए इजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ई॰पी॰सी॰) मोड के माध्यम से त्री बोली प्रणाली।

कार्य का नाम : एसवीपीएमसी मे विभिन्न स्थानो पर अलग–अलग क्षमता के विकेंद्रीकृत एसटीपी।

धरोहर राशि : रु. 51,10,564/– एवं कार्य समाप्ति की अवधि :: 11 माह।

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय : 01/12/2026 के पूर्वाहन 10.00 बजे।

निविदा प्रकाशन की तिथि : 10.11.2026 के अपराहन 3.00 बजे

निविदा दस्तावेज डाउनलोड प्रारंभ तिथि : 10.11.2026 के अपराहन 3.00 बजे

निविदा पूर्व बैठक : 01.12.2026 के अपराहन 3.30 बजे

निविदा जमा करने की तिथि : 15.12.2026 के अपराहन 3.00 बजे

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 22.12.2026 के अपराहन 3.00 बजे

निविदा खोलने की तिथि : 22.12.2026 के अपराहन 3.30 बजे

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते है।

TENDER ID : 2026_APWD_25858_1

कार्यपालक अभियंता, कार्यशाला मण्डल
अ॰लो॰नि॰वि॰, श्री विजय पुरम

पुनः निविदा सूचना

संख्या : 10-1/GPW/QUOT/OS/2026-27/121 दिनांक : 16/07/2026

ग्राम पंचायत, वन्डूर, फरारगंज तहसील, दक्षिण अण्डमान के प्रधान की ओर से पंचायत सचिव, 'मानवशक्ति (आउटसोर्सिंग) की आपूर्ति' के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत श्रम ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से 'दो–बोली प्रणाली' (अर्थात् तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली) के माध्यम से ई–टेंडर आमंत्रित करते हैं।

प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

निविदा पहचान संख्या : 2026_RDPRI_24508_1 (तारीख : 01/09/2026)

प्रधान,
ग्राम पंचायत, वन्डूर

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रमुख, पंचायत समिति, प्रात्रापुर की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर(सीसीए)/2026–27/149

कार्य का नाम : समिति द्वारा सिप्पीघाट 02 में मौजूदा ग्रामीण सड़क से उज्ज्वल टोप्पो के घर तक सड़क का निर्माण कार्य (दूसरी कॉल)।

अनुमानित लागत : रु. 7,98,322/–, धरोहर राशि : रु. 15,966/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 17/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25454_2

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, होप टाउन की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/174

कार्य का नाम : होप टाउन, ग्राम पंचायत के अंर्तगत नॉर्थ बे वार्ड संख्या 02 में अप्पा राव के घर से एम.पी. आनंद के घर तक सी सी फुटपाथ, ड्रेन और रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 7,89,451/–, धरोहर राशि : रु. 15,789/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 16/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25879_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES
Andaman and Nicobar Administration, Sri Vijaya Puram

e-Tender Notice

No. Proc-181/2/2026-IT SECTION-SS-SHIP_AN/ Date 11.11.2026

It is hereby informed to all prospective bidders that an e-Tender bearing Tender ID No. 2026_DSS_25820_1 has been published on the e-Procurement Portal of the Andaman and Nicobar Administration (https://eprocure.andamannicobar.gov.in) for "Supply, Installation, Testing and Commissioning of Public Address (PA) System at Marine Dockyard Campus, Sri VijayaPuram."

The details of the tender are as follows:

Key Events	Description
Tender ID	2026_DSS_25820_1
Name of Work	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Public Address (PA) System at Marine Dockyard Campus
Earnest Money Deposit (EMD)	Rs. 38,000/-
Last date for seeking clarification on the tender	20/11/2026
Last date and time for submission of bids	25/11/2026 up to 04:30 PM
Date and time of opening of technical bids through the e-Procurement Portal	25/11/2026 at 05:00 PM

All prospective bidders are requested to visit the e-Procurement Portal of the Andaman and Nicobar Administration (https://eprocure.andamannicobar.gov.in) and submit their bids within the stipulated timeline, in accordance with the terms and conditions of the tender.

Officer In-Charge (IT)

नशा मुक्त भारत अभियान के छह साल पूरे, 35.84 करोड़ लोगों तक पहुंचा जागरूकता कार्यक्रम

नई दिल्ली, 11 नवम्बर (हि.स.)। देश में नशे की समस्या से निपटने और लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किए गए 'नशा मुक्त भारत अभियान' के छह साल पूरे हो गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, 10 नवंबर 2026 तक यह अभियान 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। इनमें 14.33 करोड़ से अधिक युवा और 11.32 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। अभियान के तहत नशामुक्ति मित्र के रूप में दो लाख से अधिक नागरिक भी जुड़ चुके हैं।



यह अभियान 15 अगस्त 2020 को देश के 272 संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था। बाद में अगस्त 2022 में इसका विस्तार 372 जिलों तक किया गया और 15 अगस्त 2023 से इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। मंत्रालय के अनुसार, छह वर्षों में यह अभियान एक सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर जनभागीदारी वाले जनआंदोलन का रूप ले चुका है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2018 में किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, देश में सात करोड़ से अधिक लोग नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित थे। इनमें करीब 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं। इसी चुनौती से निपटने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय नशा मांग में कमी कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) के तहत यह अभियान शुरू किया था।

अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में 33.57 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। वर्ष 2021 में इसकी पहुंच करीब 1.4 करोड़ लोगों तक थी, जो अब बढ़कर 35.84 करोड़ से अधिक हो गई है। नवंबर 2025 में अभियान के पांच वर्ष पूरे होने पर अमृतसर में आयोजित कार्यक्रमों में 2.10 लाख से अधिक स्थानों पर छह करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था।

राष्ट्रीय नशा मांग में कमी कार्ययोजना का उद्देश्य नशे की मांग कम करने के लिए जागरूकता, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था करना है। इसके साथ ही नशे की लत से प्रभावित लोगों के प्रति सामाजिक भेदभाव और कलंक को कम करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है, ताकि वे दोबारा समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर तीन स्तरीय निगरानी एवं समन्वय व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन एवं निगरानी समिति, जिला स्तर पर जिलाधिकारी या उपायुक्त की अध्यक्षता में नशा मांग में कमी समिति और ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति काम करेगी। ये समितियां जागरूकता गतिविधियों, उपचार केंद्रों, पुनर्वास सेवाओं और स्वयंसेवकों के कार्यों की निगरानी करेंगी।

सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने बढ़ाया सहयोग

नई दिल्ली, 11 नवम्बर (हि.स.)। भारत और अमेरिका मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क का पता लगाने और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को अवैध आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंचने से रोकने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं।

व्हाइट हाउस ने दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी बयान में यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय (ओएनडीसीपी) के अनुसार, 2 और 3 नवंबर को नई दिल्ली में भारत–अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हुई। इसमें खुफिया सूचनाओं के आदान–प्रदान, समन्वित कानून प्रवर्तन अभियानों और दवा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने तस्करी के उभरते खतरों और मादक पदार्थों की मांग कम करने के उपायों पर भी चर्चा की।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई ओएनडीसीपी की कार्यवाहक उप निदेशक डेबी सेगुइन ने की।

ओएनडीसीपी की निदेशक सारा कार्टर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को बाधित करने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थों को वैश्विक बाजारों में पहुंचने से रोकने के लिए दोनों देशों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देश सहयोग के वादों से आगे बढ़कर व्यावहारिक कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध रासायनिक पदार्थों की आपूर्ति रोकने, वाणिज्यिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और इनका दुरुपयोग करने वाले तस्करी गिरोहों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार ने लिथियम–आयन ब्लैक मास सहित बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 11 नवम्बर। सरकार ने प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें लिथियम–आयन बैटरी का ब्लैक मास भी शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति में बदलाव किया है।

अधिसूचना के मुताबिक, "आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप तथा इस्तेमाल की जा चुकी प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर, जो बिना छांटे हुए हैं और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है (लिथियम–आयन बैटरी ब्लैक मास), की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है।" इसमें कहा गया कि यह संशोधन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है। इस अधिसूचना पर विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत अंतरिम प्रावधान लागू होंगे।

सरकार का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। यह राशि पांच वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी।

'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' का उद्देश्य भारत में घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास करना, देश के भीतर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना है। यह योजना वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक लागू रहेगी। इसके तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से समुद्र का पानी हुआ अधिक खारा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा

बेंगलुरु, 11 नवम्बर। साइंस जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक नए अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साल 2015 के बाद से अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ में आई भारी गिरावट के कारण महासागरों के एक बड़े हिस्से में दशकों से चला आ रहा मीठे पानी का रुझान उलट गया है। इसके चलते समुद्र का यह पानी अब अधिक खारा और घना हो रहा है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बदलाव से महासागरों की परतदार संरचना बिगड़ सकती है, जिससे गहरे समुद्र में दबा कार्बन आसानी से वायुमंडल में बाहर आ सकता है और ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार और तेज हो सकती है।

बता दें कि यह महत्वपूर्ण रिसर्च भारतीय विज्ञान संस्थान, मेलबर्न विश्वविद्यालय और साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर की है। अध्ययन में अंटार्कटिक इंटरमीडिएट वाटर में आए बदलावों की जांच की गई है। यह पानी दक्षिणी महासागर में बनता है और सतह से सैकड़ों मीटर नीचे बहते हुए उत्तर की ओर अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों तक फैलता है।

महासागर की इस प्रक्रिया के पीछे समुद्री बर्फ और मीठे पानी का चक्र जुड़ा हुआ है। इस बात को ऐसे समझिए कि हर साल अंटार्कटिका की सर्दियों मई से जुलाई में भारी मात्रा में समुद्री बर्फ बनती है। जैसे–जैसे तापमान बढ़ता है,



यह बर्फ पिघलती है और मीठा पानी छोड़ती है, जिससे सतह के पास ठंडे और मीठे पानी की एक परत बनी रहती है। जब समुद्री बर्फ कम होने लगी, तो समुद्र में आने वाले मीठे पानी की मात्रा घट गई। इसके साथ ही समुद्र की गहराइयों से गर्म और खारे पानी का ऊपर आना बढ़ गया। इन दोनों कारणों से AAIW में जाने वाला पानी अब ज्यादा खारा और भारी हो रहा है।

गौरतलब है कि शोधकर्ताओं की टीम ने शुरू में हिंद महासागर क्षेत्र में मध्यम गहराई वाले पानी के बहने और मिलने के तौर–तरीकों का अध्ययन करना शुरू किया था। लेकिन जब उन्होंने आंकड़ों की गहराई से जांच की, तो उन्हें अंटार्कटिका की बर्फ और इस पानी में आए बदलावों के बीच गहरा संबंध नजर आया।

कोस्टल गेटवे के लिए एक्सप्लोर करें भारत की ये शानदार जगहें

नई दिल्ली, 11 नवम्बर। समुद्र की लहरें, रेत और क्षितिज पर डूबते सूरज को देखने का जो मजा है, वो शायद ही किसी और चीज में मिलता हो। भारत के पास लगभग 11 हजार किलोमीटर लंबा कॉस्टलाइन है, जहां आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजारे देखने को मिल सकते हैं।

अगर आपको भी समुद्र की लहरों के देखना पसंद है और किसी कॉस्टल गेटअवे पर जाना चाहते हैं, तो भारत की ये जगहें आपके लिए बेस्ट हैं। इन जगहों पर आप प्रकृति की खूबसूरती देखने के साथ–साथ कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। आइए जानें भारत की इन खूबसूरत जगहों के बारे में।

गोवा– गोवा भारत में कॉस्टल गेटअवे के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगहों में से एक है। यहां सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स और दोस्तों हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। नॉर्थ गोवा वॉटर स्पोर्ट्स और शानदार नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है। वहीं साउथ गोवा शांत और रोमांटिक पलों के लिए मशहूर है। यहां का सी–फूड और कैफे कल्चर काफी मशहूर है।

अंडमान तथा निकोबार– अगर आप क्रिस्टल क्लियर पानी और सफेद रेत पर अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो अंडमान–निकोबार सबसे बेहतरीन गेटअवे है। हैवलॉक द्वीप का राधानगर बीच दुनिया के सबसे खूबसूरत तटों में गिना जाता है। यहां स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करते वक्त रंग–बिरंगी समुद्री दुनिया देखना किसी सपने जैसा लगता है।



लक्षद्वीप– भीड़–भाड़ से दूर, पूरी तरह से शांत माहौल की तलाश करने वालों के लिए लक्षद्वीप एक बेहतरीन हॉलीडे डेस्टिनेशन है। अगत्ती द्वीप की लैगून का फिरोजी पानी और शांत वातावरण इसे भारत का मालदीव बनाते हैं।

कन्याकुमारी– भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी स्थित है, जहां से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम देख सकते हैं। यहां से सनसेट और सनराइज का खूबसूरत नजारा देखना काफी अलग एक्सीपीरिएंस होता है।

विशाखापट्टनम– आंध प्रदेश का विशाखापट्टनम उन शहरों में से एक है, जहां से हरे–भरे पूर्वी घाट की पहाड़ियां और बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट को साथ मिलते देख सकते हैं। यहां आपको समुद्री तटों पर नारियल के पेड़ आदि देखने को नहीं मिलता, बल्कि यहां आपको प्री–हिस्टॉरिक एरा की खूबसूरती देखने को मिलेगी।